हुये भी उर्वरकों का उपयोग करना लाभप्रद श्रमुभव करते हैं"।

इसी संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूँ कि नए किस्म के बीज हैं इनको ले कर केवल एक प्रति-शत किसान ही वो संकते हैं या जिन के पास भरपूर सिंचाई का प्रबन्ध है बही वो सकते हैं क्या यह सही नहीं है? यदि यह सही है तो सामान्य किसान को क्या सरकार सस्ते उर्वरक देने का प्रयास कर रही है।

श्री जगजीवन राम: अभी तक सिंचाई के क्षेत्र में और अच्छे बीज लगाने वाले जो किसान हैं उनको जितने की जरूरत होती है वह भी देश में पैदा होने वाले और बाहर से मंगाये जाने वाले खाद से पूरी नहीं होती है, उनको भी पर्याप्त मात्रा में वह नहीं मिल पाती है। यह सही है कि उसके बाहर के किसानों को कोई अच्छी मात्रा में लाद उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।

SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH: The distribution of fertilisers is done by the State, but the Centre is concerned with higher foodgrain production. May I know whether Government is aware that the distribution, particularly of nitrogenous fertilisers, in various States and in Gujarat in particular, being made through the co-operative societies is not reaching the farmers and whether he would consider advising the State Governments to supply nitrogenous fertilisers not only through co-operative societies...

MR. SPEAKER: From U.P., the hon. member is going to other States.

SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH: It is a general question about all States.

MR. SPEAKER: Unfortunately the main question relates to U. P.

श्री महाराज सिंह मारती: मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि आगे चल कर जब उत्पादन वढ़ जाएगा तब कीमतें नीचे श्रा जायेंगी। जहां तक पोटाश की खाद का सम्बन्ध है इसको ग्राप हमेशा इम्पोर्ट करेंगे । इस वास्ते उसकी कीमत नीचे श्राने का सवाल ही पैदा नहीं होता है । जितनी ग्रागे ग्रापकी फैक्ट्रियों में खाद का उत्पादम होगा। उस उत्पादन के सत्तर प्रतिशत पर कोई मूल्यों पर श्रापका नियन्त्रण नहीं होगा। ग्रापने जो यह कहा है स्टेटमेंट में कि श्रागे पैदावार बढ़ेगी तो इससे क्या कीमत श्राप समकते हैं कि कम हो जाएगी ? क्या ग्राप यह समकते हैं कि जितनी मांग होगी उससे ज्यादा पैदावार श्राप करने जा रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम: जितनी मांग होगी उससे ज्यादा पैदा करने हम जा रहे हैं यह दाबा तो मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मांग तो बराबर बढ़ने वाली है और जैसे जैसे किसानों में इस बीज की पहुँच होती जाएगी, नए बीजों की, पानी की तो खाद की बहुत ज्यादा मांग होगी। इस में मी शंक नही है कि दुनिया में हम सब से कम खाद इस्तेमाल करते हैं पर कैपिटा, लेकिन अभी जो कुछ हम देख रहे हैं उससे ऐसा मनता है कि जितनी हमारी फरिटलाइजर मिलिस्टरी के हाथ में स्कीमें है कारखाने खड़े करने की वे अगर खड़े हो जायेगें तो दाम अभी जो हैं उसके मुकाबले में नै वे आ जायेगे।

Commercialisation of Indian Agriculture

*1455. SHRI SHIVA CHANDRA JHA: SHRI KASHI NATH PANDEY:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that Indian agriculture has been more Commercialised since the First Plan period;
 - (b) if so, the details thereof; and
- (c) if not, the present percentage of commercial crops vis-a-vis that of the foodgrains production relative to what it was at the beginning of the First Plan?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM): (a) to (c). A statement is pleased on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT—1026/68].

श्री शिव चन्द्र भा: मैं जानना चाहता हूं कि कर्माशयल क्राप्स की जो पैदावार बढ़ी है यह एट दी कास्ट ग्राफ फूडग्रेंज बढ़ी है या नई जमीन को तोड़ा गया है ग्रीर वहां पर कर्माशयल क्राप्स की पैदावार की गई है इस वजह से पैदा-बार बढी है?

श्री जगजीवन राम: कुछ जगह ऐसाभी हुश्राहै। कुछ इलाके में थोड़ा अनाज वाला क्षेत्र कंम हुआ है। कुछ नए तरीके से बढ़ी है। थोड़ा सा इसका असर अनाज पर पड़ाहै।

श्री शिव चन्द्र भा: कर्माशलाइजेशन की एक लहर सी चल पड़ी है श्रीर इसकी वजह से जैसे रिशया में कुलाक्स पैदा हो गये थे इसी तरह से यहां भी कुलकाइजेशन की एक लहर चल गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही नहीं है?

श्री खगजीवन राम: यह बिल्कुल सही है कि देहातों में जो बड़े किसान हैं वे नए तरीके से ज्यादा लाभ उठा रहे हैं श्रीर जो छोटे किसान है वे उससे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यह भी ठीक है कि जो नये बीज हुए हैं या रासायनिक खाद हुई है इसका फायदा उनको अधिक पहुँचा है जिन के पास साधन है। यह तो वस्तु-स्थित है।

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH: Is the Government aware that even in the case of commercial crops, the economy is so deficient that there is large scope not only for increase in production of commercial crops in competition with foodgrains, but along with foodgrains? To achieve this end, does the Government propose to encourage, not commercialisation, but acceptance of the basic commercial principle of recognising agriculture as an industry and treating it as such?

SHRI JAGJIWAN RAM: That is the whole trend. With the new strategy in agriculture, we are lifting it from the subsistance stage to commercial or paying stage.

श्री हुकम चन्द कछवाय: मैं जानना चाहता हूँ कि इन फसलों के बारे में भी मंत्री महोदय वही नीति ग्रपनाने जा रहे हैं जो कि उन्होंने ग्रनाज के बारे में ग्रपनाई है? होता यह है कि ये फसलें जब ग्राती हैं तो जो बड़े व्यापारी हैं वे इनको बहुत सस्ते दामों पर ले कर इन्हें बहुत ऊंचें दामों पर बेचते हैं ग्रीर ज्यादा मुनाफा कमाने हैं। इस मुनाफे में कमी हो सके ग्रीर काश्तकार को उचित ग्रीर ग्रधिक दाम मिले सके, इसके लिए क्या कोई विशेष नीति ग्रपनाने जा रहे हैं?

श्री अगजीवन राम: इस पर तो बराबर विचार होता रहता है कि ऐसा कोई इंतजाम रहे कोग्रोप्रेटिञ्ज के जिरये या कमोडिटी कार-पोरेशन के जिरये कि किसान को निर्धारित मूल्य मिल सके श्रीर फसल के वक्त पर व्यापारी सस्ते दामों पर खरीद कर बेमुनासिव मुनाफा न उठा संकें।

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA: In view of the large imbalance between the price ratio of commercial crops vis-a-vis foodgrains, there is likerihood of diversion taking place, as it happened recently in sugarcane. Has the Government devised any scheme by which the relative stability of commercial crops and foodgrains may be maintained to avoid this diversion, which affects our total production capacity?

SHRI JAGJIWAN RAM: Constant exercises are done on that question so that we can have something like a price parity between various agricultural commodities. But I will not claim that any very satisfactory solution has been yet found.

Food Corporation of India

- *1456. SHRI PREM CHAND VERMA: Will the Minister of FOOD AND AGRI-CULTURE be pleased to state:
- (a) the quantity of foodgrains which has been handled by the Food Corporation